

प्रेषक,

अनूप वधावन,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,  
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 18 दिसम्बर, 2009

विषय: आगामी कुम्भ मेला, 2010 के अन्तर्गत हरिद्वार स्थित सिंहद्वार के निकट पुराने सेतु के 35.00 मी० अपस्ट्रीम में अपर गंगा कैनाल पर 80मी० स्पान स्थाई सीमेन्ट कंक्रीट सेतु के निर्माण के कार्यों की पुनरीक्षित प्रशासकीय, वित्तीय तथा अवशेष धनराशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1036/IV(1)/2009-178(कुम्भ)/2009 दिनांक 25.9.2009 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन रु० 498.15 लाख के सापेक्ष तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु० 424.22 लाख (रुपये चार करोड़ चौबीस लाख बाईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तत्कम में आपके पत्र संख्या-2655/कु०मे०/लोनिवि०/सिंहद्वार सेतु दिनांक 04.11.2009 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा उक्त स्वीकृत कार्य हेतु प्रेषित संशोधित आगणन रु० 450.39 लाख के सापेक्ष तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु० 437.31 लाख (रु० चार करोड़ सैंतीस लाख इकत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए इसके विपरीत पूर्व स्वीकृत रु० 424.22 लाख को कम करते हुए स्वीकृत एवं अवशेष रु० 13.09 लाख (रुपये तेरह लाख नौ हजार मात्र) की धनराशि को भी वित्तीय वर्ष 2009-10 में आहरित/व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उक्तानुसार संशोधित/पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति अपवादस्वरूप निर्गत की जा रही है एवं इसका किसी अन्य निर्माण कार्य की स्वीकृति के संबंध में दृष्टान्त के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का वास्तविक आवश्यकतानुसार किशतों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही अगली किशत का कोषागार से आहरण किया जाएगा। यदि पूर्व अवमुक्त धनराशि बैंक में रखकर उस पर ब्याज अर्जित हुआ है तो उस समस्त अर्जित ब्याज को राजकोष में ट्रेजरी चालान से जमा करके उसकी फोटोप्रति शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का दायित्व मेलाधिकारी का ही होगा।
3. चूंकि निविदा में प्राप्त एल-1 निविदा आधार पर स्वीकृत लागत से कम धनराशि व्यय होना संभावित है। अतः न्यूनतम सम्भावित व्यय के अनुसार ही कम धनराशि आहरण की जायेगी तथा आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि बचत होती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा।
4. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किया जायेगा और आगणन का पुनरीक्षण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
5. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए यथाआवश्यकता, निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए।
6. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
7. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गई है।



8. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।
9. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
10. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।
11. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु उप परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र०रा०सेतु निगम एवं मेलाधिकारी, हरिद्वार पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
12. शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त शासनादेश दिनांक 25.9.2009 के अनुसार लागू रहेंगे।

2— इस संबंध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या 1614/IV(1)/2009-39(साम०)/2006-टी०सी० दिनांक 24.11.2009 के द्वारा मेलाधिकारी, हरिद्वार के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू० 100.00 करोड के सापेक्ष किया जायेगा एवं पुस्तांकन तदुस्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 630/XXVII(2)/2009 दिनांक 18 दिसम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(अनूप वधावन)  
सचिव।

संख्या : 1772 (1)/IV(1)/2009 तददिनांक 18/12/09

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
11. उप परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र०राज्य सेतु निगम लिमि०, सेतु निर्माण इकाई, हस्तिनापुर, मेरठ।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
(अनूप वधावन)  
सचिव।